

विचार

ग्राउंड जीरो पर बाल कल्याण क्षेत्र में ‘यूनिसेफ’ की भूमिका बहुत रीन

बाल कल्याण की बात हो या उनके अधिकारों की रक्षा, दोनों में प्रहरी की भूमिका निभाती है 'यूनिसेफ'। इसलिए यूनिसेफ का नाम सुनते ही मन-मस्तिष्क में बच्चे दृढ़ गिर्द घूमने लगते हैं। साथ ही उनकी समस्याओं और सुधारी प्रयासों का जिक्र भी होने लगता है। आज 'विश्व यूनिसेफ दिवस' है। एक ऐसी संस्था जो संसार के 190 देशों के बेहद दुर्गम स्थानों पर पहुंचकर कर बच्चों के अधिकारों की हिमायत के लिए मजबूती से लड़ती है। बाल कल्याण की सुविधाएं विश्व के प्रत्येक जरूरतमंद, कमजोर और वंचित बच्चों तक पहुंचे, इसलिए लिए यूनिसेफ की टीमें चौबीसों घंटों ग्रांउड जीरो पर तैनात रहती हैं। यूनिसेफ का मतलब होता है 'संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष' जिसका आरंभ 11 दिसंबर, 1946 को 'संयुक्त राष्ट्र महासभा' द्वारा किया गया था। शुरूआती वक्त में संस्थान में मात्र 43 देश शामिल हुए थे, लेकिन कुछ वर्षों बाद ये संख्या 100 पार कर गई। पर, आज इस संस्था में 190 मुल्क जुड़े हैं। संख्या में धीरे-धीरे इजाफा हो रहा है। यूनिसेफ के 5 लाख प्रतिनिधि इस समय परे संसार में कार्यरत हैं। वहीं, भारत में 18 हजार के करीब वर्कर दुर्गम स्थानों पर बाल कल्याण के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बाल तस्करी की रोकथाम में इनकी अगल से टीमें कार्य करती हैं।

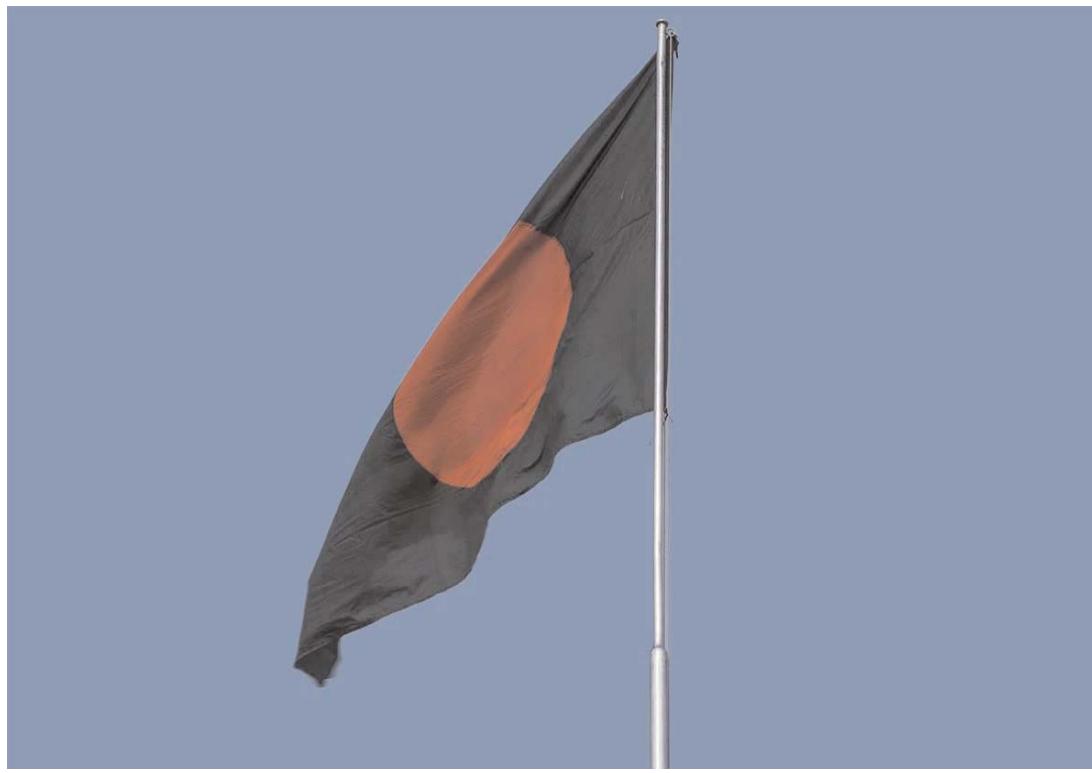
हिंदुस्तान में रोजाना करीब 69,000 बच्चे पैदा होते हैं। उन सभी नौनिहालों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और बाल संरक्षण में यूनिसेफ इंडिया बेहतरीन कदम उठाने को संकल्पित होता है। मौजूदा समय में यूनिसेफ की टीमें युद्धग्रस्त यूक्रेन-रूस, ईरान-इराक, अफगानिस्तान जैसे मुल्कों में अधिकांश जुटी हैं। वहाँ अभावग्रस्त बच्चों की परवरिश करने के अलावा उनकी शिक्षा-स्वास्थ्य में लगे हैं। वैसे देखा जाए तो, विश्व को यूनिसेफ की कार्यशैली द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तब ज्यादा दिखी, जब इनके योद्धाओं ने बिना अपनी जान की परवाह किए युद्ध से आहत, असहाय, बेघर बच्चों को जरूरती सामानों की आपूर्ति, विभिन्न किस्म की सहायताएं और स्वास्थ्य में सुधार के अभियानों को चलाया। जैसे-जैसे समय बदला, यूनिसेफ ने अपनी कार्यशैली में और बदलाव किए। पहले इनका काम सिर्फ बाल अधिकारों की रक्षा के लिए जाना जाता था। लेकिन उसके बाद बच्चों के बेहतर जीवन को बनाने का भी जिम्मा इन्होंने अपने कंधों पर उठा लिया। फिलहाल वक्त में, यूनिसेफ की टीमें माताओं और नवजात शिशुओं के लिए एचआईवी की रोकथाम और उपचार, पर्याप्त पानी, स्वच्छ वातावरण, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, बाल स्वास्थ्य व पोषण जैसे क्षेत्रों में भी कार्यरत हैं।

बांग्लादेश- कटुरपंथी जमात के निशाने पर हिंदुओं का जान-माल, सुरक्षा के लिए भारत सरकार करें पहल

दीपक कुमार त्यागी

बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 की दोपहर को हुए शेख हसीना की सरकार के ततापलट के बाद से ही वहाँ की कटूरपंथी जहरीली जमात के द्वारा हिंदुओं के जान-माल व मंदिर को चुन-चुन कर के निशान बनाया

जा रहा है, इन कट्टरपंथियों के द्वारा हिंदुओं के जान-माल को तब से ही जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि ततापलट के बाद बहुत सारे लोगों को यह उमीद थी कि अब देश में नोबेल पुरस्कार प्राप्त मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतर्रिम सरकार का गठन होने के बाद वहाँ के हाल धीरे-धीरे पूरी तरह से सुधर जायेंगे। लेकिन अफसोस मोहम्मद यूनुस तो भारत व हिंदूओं के विरोध में अंधे होकर के खुद इन कट्टरपंथियों की गोद में जाकर बैठ गये हैं और कई माह बीतने के बाद भी बांग्लादेश के हालात सुधरने की ज़राब हो गये हैं।



देश व दुनिया के मीडिया के सूत्रों से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की हजारों की संख्या में जघन्य अपराध वाली घटनाएं घटित हो चुकी हैं, हिंदू इन घटनाओं में अपनी अनमोल जान-माल को गंवा रहे हैं, जो बांग्लादेश के अंदरुनी भयावह हालात के बारे में बताने के लिए काफी हैं। मीडिया हिंदुओं को चुन-चुन कर के निशाना बनाया जा रहा उस वक्त इन लोगों की पूरी जमात की जबान से एक शब्द भी हिंदुओं की रक्षा की अपील तक के लिए नहीं निकल रहा है, जो स्थिति हम सभी सनातन धर्म के अनुयायियों व देश के सभी नीति-निर्माताओं के लिए चिंताजनक व विचारणीय है।

स्रोतों से जो खबरें लोगों को निरंतर मिल रही हैं, वह देश व दुनिया के सभी हिंदुओं के साथ-साथ इंसान व इंसानियत को बहद बुरी तरह से झकझोर देने वाली है। क्योंकि तथ्यापलट के बाद से बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के द्वारा भारत विरोध व हिंदुओं के जान-माल को जानबूझकर जमकर के निशान बनाया जा रहा है। हिंदुओं को मोहम्मद यूनुस सरकार के संरक्षण प्राप्त इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा सरेआम मौत के घाट तक उतारा जा रहा है। वहां हिंदुओं के मंदिर, मकान, दुकान व फेक्ट्रीयों आदि को तोड़फोड़ कर के बड़े पैमाने पर आग के हवाले खुलेआम किया जा रहा है और अफसोस की बात यह है कि बांग्लादेश की पुलिस-फोर्स नियम-कायदे व कानून के अनुसार मानवता की रक्षा ना करके खुलम-खुला इन भारत व हिंदुओं की विरोधी कट्टरपंथियों की जमात का साथ दे रही है। लोकिन इस हाल में हम भारतवासियों के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि पूरे विश्व के किसी भी कौनें में अगर इस्लाम धर्म के किसी व्यौक्ति के साथ किसी अच्छी धर्म

के व्यक्ति के द्वारा कोई अप्रिय घटना घटित कर दी जाती है, तो हमारे पायरे देश भारत तक में भी इस्लामिक कठूरपंथियों के इशारे पर उनके बहुत सारे लोगों को जमकर सड़कों पर बहाल काटते देखा जाता है। लेकिन अब जब बांग्लादेश में

सुरक्षा करने की मांग को लेकर व हमले के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर के पूरे बांग्लादेश में जगह जगह छोटे-बड़े विरोध प्रदर्शन निरंतर कर रहा है। जिन प्रदर्शनों में हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास बढ़-चढ़कर के भाग ले रहे थे और वह पूरे बांग्लादेश में धूम-धूमकर अत्याचार के खिलाफ हिंदुओं को संगठित कर रहे थे और भारत व दुनिया से बांग्लादेश के हिंदु संत चिन्मय कृष्ण दास बांग्लादेश की मोहम्मद युनस सरकार की आंखों का कांटा बने हुए थे, जिसके चलते ही हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को बांग्लादेश सरकार के इशारे पर गिरफ्तार कर लिया गया था और वहाँ के न्यायालय में हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की आवाज उठाने वाले अधिवक्ता पर भी जानलेवा हमला करके व उसके चैंबर में तोड़फोड़ करके उसको भी निशाना बनाया गया था।

वहीं बांग्लादेश के मुद्रे पर हाल ही में एक नियमित प्रेस ब्रीफिंग में सबाल पूछे जाने पर अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा था कि - हम इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान होना चाहिए। सरकारों को कानून के शासन का सम्मान करने की आवश्यकता है, उहाँ आधारभूत मानवाधिकारों का सम्मान करने की आवश्यकता है। हम इस बात पर हमेशा जोर देते रहेंगे। किसी भी तरह का विरोध शांतिपूर्ण होना चाहिए। हम इस बात पर बल देते हैं कि हिरासत मैं लिए गए लोगों को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और उनसे अधारभूत मौलिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के अनुरूप व्यवहार किया जाना चाहिए। हालांकि उनका यह बयान औपचारिकता मात्र है, हालांकि उनके इस बयान में भी बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कोई ठोस आश्वासन या समाधान नज़र नहीं आता है, उनका बयान केवल एक औपचारिकता मात्र है।

जाता है, उनका बयान कवल एक आपचारिकता मात्र है। वर्हीं हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यनुस पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में नाकामयाबी दिखाई है, शेख हसीना ने मोहम्मद यनुस पर आरोप लगाया कि उन्होंने हिंदुओं के नरसंहार में संक्रिय रूप से भाग लिया है। शेख हसीना के इस बयान को दुनिया भर के ठेकेदार बनने वाले ताकतवर देशों व मानवाधिकार संगठनों को संज्ञान लेकर के हिंदुओं के नरसंहार को रोकने के लिए मोहम्मद यनुस सरकार के खिलाफ वैश्विक स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए, जो पर अभी तक तो कोई पहल होती हुई नज़र नहीं आ रहा है।

हालांकि भारत सरकार भी बार-बार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को विभिन्न फोरम पर उठाने का कार्य निरंतर कर रही है, लेकिन उसके बाद भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर कट्टरपंथियों की जमात के द्वारा जबरदस्त अत्याचार जारी हैं और हमारे देश के धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदार बन चुके लोगों की जमात इस बेहद ज्वलत मुद्दे पर चुपचाप बैठकर के अब भी तमाशा देख रही है, वह जम्मू-कश्मीर के हिंदुओं की तरह ही बांग्लादेश हिंदुओं को भी तिल-तिल कर मरते हुए देख रही है, जो बांग्लादेश चंद माह पहले छात्रों के विस्क आंदोलन में जल रहा था, वहां तख्तापलट के तुरंत बाद से ही भारत वह हिंदुओं के त्रणों की भूलकर के छात्रों का यह हिंसक आंदोलन हिंदू विरोधी आंदोलन में अचानक कैसे तब्दील हो गया है, देश व दुनिया के विशेषज्ञों को इस स्थिति का निष्पक्ष रूप से आंकलन करने चाहिए कि आखिरकार किस के उकसावे पर बांग्लादेश में अचानक से स्थिति भारत व हिंदुओं के विरोधी कैसे हो गयी। विचारणीय यह है कि आरक्षण के विरोध की आग में झुलसता हुए बांग्लादेश अचानक से भारत व हिंदू विरोध की आग में कैसे झुलसा। तख्तापलट के बाद भी हिंसा आज भी अनवरत रूप से जारी है, लेकिन अब दंगा-फसाद में चिन्हित करके हिंदुओं को मौत के घाट उतारना जारी है। हिंदुओं की सुरक्षा की दृष्टि से पूरे बांग्लादेश में जबरदस्त अस्थरता का माहौल व्याप्त है, मीडिया सूत्रों के अनुसार दर्शकों को मोहम्मद युनुस सरकार के द्वारा सरकारी सरक्षण मिलने के चलते हिंदुओं के जान-माल की भारी क्षति होना अब भी निरंतर जारी है। जिसके चलते बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ-साथ पूरी दुनिया के हिंदू अब भारत के प्रधानमंत्री ने रेन्ड्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर प्रसाद के साथ-साथ एनएसए अजीत डोभाल की तरफ बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा करने की उम्मीद से देख रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि भारत सरकार अब बयानबाजी से इतर होकर के धरातल पर ठोस कदम उठाकर के तत्काल बांग्लादेश में भारत विरोधी सभी गतिविधियों व हिंदुओं के नरसंहार पर नकेल करेंगी।

इंडिया गढ़बंधन की रार से कांग्रेस से ज्यादा क्षेत्रीय दलों को होगा नुकसान

कमलेश पांडे

कांग्रेस के नेतृत्व वाले %ईंडिया गठबंधन% में नेतृत्व के सवाल पर जो मौजदा चिल्ह-पों मची हुई है और लोकसभा में नेता प्रतीक्षण राहुल गांधी के नेतृत्व पर एक बार फिर से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उससे न तो तुष्णमूल कांग्रेस नेत्री व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का राजनीतिक भला होने वाला है और न ही उनकी सुर में सुर मिलाने वाले एनसीपी शरद पवार के शरद पवार-सुप्रिया सुले, शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे-आदित्य ठाकरे, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव-रामगोपाल यादव या आप पार्टी के अररिवंद केजरीवाल आदि जैसे नेताओं का। हाँ, इससे कांग्रेस आई की उस सियासी साख को धक्का अवश्य लगेगा, जो कि बमुश्किल उसने राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव 2024 के बाद हासिल कर पाई है।

हासल कर पाइ ह। राजनीतिक मामलों के जानकारों का स्पष्ट कहना है कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के लिए हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा की हार जरूर मायने रखती है, क्योंकि यह जीती हुई बाजी हारने के जैसा है। लेकिन सिफ़ इसको लेकर ही इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस से छीन लेना कोई राजनीतिक बुद्धिमानी का काम प्रतीत नहीं होता है। शायद कांग्रेस भी इसे नहीं मानेगी और किसी भी राष्ट्रीय दल को क्षेत्रीय दलों के सामने चुटने भी नहीं टेकने चाहिए, यदि सत्ता प्राप्ति के लिए संख्या बल का खेल नहीं हो तो! बीजेपी भी यही करती है और अपने गठबंधन सहयोगियों को उनकी वाजिब औकात में रखती है। तीसरे-चौथे मोर्चे की विफलता के पीछे भी तो अनुशासनहीनता या अतिशय महत्वाकांक्षा का खेल ही तो था, जिसे



आपसी तालमेल की कमी की वजह से इसकी कई बार आलोचना भी होती रही है। इसी वजह से इसके प्रमुख सूत्रधार रहे जदयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना पाला बदल लिया और भाजपा के खेमे में चले गए। वो भी इंडिया गढ़बंधन के संयोजक का पद पाना चाहते थे, जो लालू प्रसाद के परोक्ष विरोध के चलते सम्भव नहीं हो पाया। ऐसे में संभव है कि ममता भी एकबार फिर से तीसरे मोर्चे को मजबूत करने की पहल करें

और नीतीश की तरह ही इंडिया गठबंधन को टाटा, बाय-बाय कर दें।

उल्लेखनीय है कि ममता बनर्जी का यह बयान उनकी पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा कांग्रेस और अन्य इंडिया ब्लॉक सहयोगियों को लेकर दिए बयान के बाद सामने आया है। तब कल्याण बनर्जी ने कहा था कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक को अपने अहंकार को अलग रखना चाहिए और ममता बनर्जी असफलताओं का समना करना पड़ा आर उनकी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। जबकि कांग्रेस इंडिया ब्लॉक की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसे अक्सर गठबंधन का वास्तविक नेता माना जाता है। यही वजह है कि टीएमसी ने लगातार ममता बनर्जी को गठबंधन की बागडोर संभालने की वकालत की है।

